

# लेखाशास्त्र

## अध्याय-2: लेखांकन के सैद्धांतिक आधार



## लेखांकन के सिद्धांत

लेखांकन के सिद्धांत वे नियम हैं, जिनका उपयोग करके एक लेखापाल व्यापार के वित्तीय विवरण एवं लेखों को तैयार करता है। लेखांकन सिद्धांत के दिशा-निर्देश होते हैं, जिनकी सहायता से लेखाकर्म को अधिक व्यावहारिक एवं सर्वमान्य बनाया जाता है।

लेखांकन कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कर उसे वैश्विक रूप में सर्वमान्य बनाने के लिए लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। यद्यपि इन सिद्धांतों को शासन ने किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया है और न ही ये वैज्ञानिक नियम हैं, अपितु इन्हें अपनाकर लेखांकन की विधियों में एकरूपता स्थापित की जाती है। इन सिद्धांतों के आधार पर सभी लेखापाल सामान्यतः एक निर्धारित नीति का अनुसरण करते हैं, जिससे वित्तीय विवरण परस्पर तुलनीय होते हैं और विश्लेषण हेतु एक समान आधार प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत पूरे विश्व की लेखांकन पद्धति में एकरूपता स्थापित करते हैं।

**परिभाषा :-**

**रॉबर्ट एन. एन्थोनी के अनुसार,** "लेखाविधि के नियमों तथा प्रथाओं को सामान्यतः "सिद्धान्त" कहा जाता है"।

**लेखांकन के सिद्धांत संक्षेप में**

संक्षेप में, "लेखांकन सिद्धान्त वित्तीय विवरणों एवं लेखों को तैयार करने के वे नियम हैं, जिन्हें प्रयोग कर लेखांकन कार्यो को सर्वमान्यता प्रदान की जाती है।"

## लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएँ

लेखांकन सिद्धांतों में निम्न तीन विशेषताएँ होनी चाहिए:

1. **तथ्यपरक (Objectivity)**- लेखांकन सिद्धान्त वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।  
ये व्यक्तिगत विचारों से परे हटकर निरपेक्ष होने चाहिए। ये सिद्धान्त विश्वसनीय होना

चाहिए। प्राप्त लेखा सूचनाओं की सत्यता को परखा जा सके, ऐसा गुण भी इन सिद्धान्तों में होना चाहिए।

2. **संबद्धता एवं उपयोगिता (Relevance and Usefulness)** - लेखांकन सिद्धान्त में संबद्धता का गुण होना चाहिए अर्थात् लेखा सूचनाएँ तथा उससे प्राप्त परिणाम अर्थपूर्ण एवं उपयोगी होने चाहिए। जिससे इन सिद्धान्तों को सबकी मान्यता मिल सके। लेखांकन सिद्धान्त में व्यावहारिकता होनी चाहिए, ताकि उसे
3. **व्यावहारिकता (Feasibility)**- लेखांकन सिद्धान्त में व्यवहारिकता होनी चाहिए, ताकि उसे सरलतापूर्वक व्यवहार में अपनाया जा सके।

## लेखांकन अवधारणाएं

लेखांकन सिद्धान्तों के प्रकारों को समझने के लिए, आपको पहले लेखांकन सम्मेलनों और लेखांकन अवधारणाओं को समझना होगा जो व्यवसाय लेखांकन में शामिल लेखांकन सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं। तो, आइए उन अवधारणाओं और सम्मेलनों के साथ शुरू करें जो लेखांकन प्रथाओं में ओवरलैप करते हैं, जिनमें पोपुलर लेखांकन सिद्धान्त शामिल हैं।

लेखांकन के सिद्धान्तों को रेखांकित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणाओं और सम्मेलनों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **पैसे माप की अवधारणा:**

लेखांकन में व्यावसायिक लेन-देन एक उपाय के रूप में पैसे का उपयोग करें और लेखांकन मापन में एकीकृत कारक के रूप में। वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने में आम माप इकाई के रूप में पैसे स्वीकार करने के बाद यह लेखांकन सिद्धान्त सही समझ में आता है। वित्तीय लेन-देन में उपयोग किए जाने वाले धन के लिए लेखांकन सिद्धान्त यह हैं कि केवल धन से जुड़ी घटनाओं और लेनदेन को लेखांकन लेन-देन के रूप में दर्ज किया जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग में लेन-देन में पैसे की राशि या मूल्य दिखाता है।

- **एक व्यावसायिक इकाई की अवधारणा:**

इस लेखांकन अवधारणा का कहना है कि आपकी व्यावसायिक पहचान आपकी पहचान से स्वतंत्र है। लेखांकन सिद्धान्त व्यापार के मालिक और व्यवसाय को अलग-अलग संस्थाओं

के रूप में देखता है, जो जहां तक वित्तीय लेनदेन और लेखांकन का संबंध है, अलग-अलग अलग हैं। इस प्रकार, कानूनी तौर पर, आपके नाम से व्यवसाय पर मुकदमा किया जा सकता है, या आपके व्यवसाय पर स्वतंत्र रूप से मुकदमा किया जा सकता है।

- **एक चल रहे उद्यम की अवधारणा:**

इस अवधारणा में कहा गया है कि उद्यम के वित्तीय लेनदेन को ट्रैक किया जाता है और बी को इस धारणा पर दर्ज किया जाता है कि यह अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के अलावा स्वतंत्र रूप से और बहुत लंबे समय तक ऑपरेशन में बना रहेगा।

- **लागत की अवधारणा:**

यह अवधारणा किसी संगठन की निश्चित परिसंपत्तियों के लिए नियमों को परिभाषित और सेट करती है। लागत अवधारणा में कहा गया है कि किसी संगठन की निश्चित परिसंपत्तियों का हिसाब हमेशा आइटम की मूल कीमत पर होना चाहिए और वार्षिक आधार पर इसके मूल्य का अवमूल्यन होना चाहिए। यह पहनने और आंसू, परिसंपत्ति उपयोग, दुर्घटनाओं पर आधारित है जो हो सकता है, और संपत्ति के खरीदे जाने के बाद से बीता समय, अन्य कारकों के बीच।

- **द्वंद्व की अवधारणा:**

द्वंद्व की यह अवधारणा बताती है कि एक विशिष्ट राशि के प्रत्येक क्रेडिट लेनदेन के लिए, उसी राशि के लिए एक समान डेबिट लेनदेन भी लेखांकन प्रथाओं में किया जाना चाहिए। इस आधार का उपयोग डबल-एंट्री लेखांकन प्रणाली में मूलभूत सिद्धांत के रूप में किया जाता है।

- **लेखांकन वर्ष की अवधारणा:**

यह अवधारणा या लेखांकन सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यवसाय अपने लेखांकन रिपोर्टिंग चक्र को शुरू करने और समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट अवधि चुनने के लिए स्वतंत्र है, जिसका उल्लेख इसकी रिपोर्टिंग में किया जाना चाहिए। इसे लेखांकनजी आवधिकता कहा जाता है और यह साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, छमाही या सालाना हो सकता है।

- **खर्चों के मिलान की अवधारणा:**

इस रोचक अवधारणा में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि कोई राजस्व दर्ज किया जाता है और लेखांकन में मान्यता प्राप्त है, तो राजस्व अर्जित करने में इससे संबंधित खर्चों

का भी लेखा-जोखा और मान्यता प्राप्त है। यह निर्दिष्ट लेखांकन अवधि में अर्जित लाभ का सटीक मूल्य देने के लिए किया जाता है।

- **बकाया वसूली की अवधारणा:**

लेखांकन में इस अवधारणा में कहा गया है कि जब भी किसी राजस्व लेन-देन की सूचना दी जाती है या उसका हिसाब लगाया जाता है, तो इसे अर्जित राजस्व माना जाता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका भुगतान आखिरकार कब प्राप्त हुआ। हालाँकि, प्राप्त या भुगतान की गई सभी चीजों को तब तक लाभ का लेन-देन नहीं माना जाता है जब तक कि खरीदी गई सेवाएँ या सामान खरीददार को नहीं दिया जाता है।

## लेखांकन की प्रणाली

- **नकद प्रणाली:** इस प्रणाली के तहत, वास्तविक नकद रसीदें, और वास्तविक नकदी भुगतान दर्ज किए जाते हैं। वास्तव में प्राप्त या भुगतान में नकदी तक क्रेडिट लेनदेन दर्ज नहीं किए जाते हैं। एक धर्मार्थ संस्था, एक क्लब, एक स्कूल, एक कॉलेज, आदि जैसे गैर-व्यापारिक चिंताओं के मामले में तैयार रसीदें और भुगतान खाता और वकील, डॉक्टर, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट इत्यादि जैसे पेशेवर पुरुष उद्धृत किए जा सकते हैं। नकद प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण। यह प्रणाली एक व्यापार अवधि के वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड नहीं बनाती है क्योंकि यह बकाया व्यय और बकाया आय जैसे उत्कृष्ट लेनदेन रिकॉर्ड नहीं करती है। यह प्रणाली वास्तविक नकद रसीदों के रिकॉर्ड पर आधारित है और वास्तविक नकद भुगतान किसी विशेष अवधि के लिए सही लाभ या हानि का खुलासा करने में सक्षम नहीं होंगे और किसी विशेष दिन पर व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करेंगे।
- **मर्केटाइल (संचय) प्रणाली:** इस प्रणाली के तहत, किसी अवधि से संबंधित सभी लेनदेन खाते की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं, वास्तविक रसीदों और नकदी आय के भुगतान के अलावा, देय खर्च भी दर्ज किए जाते हैं। यह प्रणाली व्यवसाय के वित्तीय लेनदेन की पूरी तस्वीर देती है क्योंकि यह अवधि से संबंधित सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाती है। यह प्रणाली वित्तीय लेनदेन के पूर्ण रिकॉर्ड पर आधारित है, जो किसी विशेष अवधि के लिए सही लाभ या हानि का खुलासा करती है और किसी विशेष दिन व्यापार की वास्तविक वित्तीय स्थिति भी प्रदर्शित करती है।

## लेखांकन का आधार:

### नकदी आधार :-

जब लेनदेन को नकद आधार पर दर्ज किया जाता है, तो वे विचार विनिमय करने पर कंपनी की पुस्तकों को प्रभावित करते हैं; इसलिए, नकद आधार लेखांकन अल्पावधि में अर्जित लेखांकन की तुलना में कम सटीक है। 1986 का कर सुधार अधिनियम सी निगमों, कर आश्रयों, कुछ प्रकार के ट्रस्टों और उन साझेदारियों के लिए नकद आधार लेखा पद्धति का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है जिनमें सी निगम भागीदार हैं।

### प्रोद्भवन आधार :-

## लेखांकन मानक

लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है- 'लेख' और 'अंकन'। जहां लेख का अर्थ "लिखने" से हैं और अंकन का अर्थ "अंक" से लगाया जाता है। इस प्रकार से व्यवसाय में जितने भी लेन-देन होते हैं उनको एक बही (Book) के रूप में लिखना ही "लेखांकन" (Accounting) कहलाता है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन को लेखाकर्म के नाम से भी जाना जाता है।

## लेखांकन मानक की आवश्यकता

- लोगों के विभिन्न समूह, जो उद्यम के प्रबंधन से पूरी तरह से तलाकशुदा (अलग-अलग) हैं, उद्यम के प्रकाशित वित्तीय विवरणों को पढ़ने और उपयोग करने में रुचि रखते हैं क्योंकि लोगों के इन समूहों को इसके मामलों में एक वैध रुचि है। कई मामलों में, उनके पास आपूर्ति की गई जानकारी का कानूनी अधिकार है।
- उद्यमों के मामलों में रुचि रखने वाले लोगों में शेयरधारकों और संभावित शेयरधारक शामिल हैं; ऋण पूंजी के आपूर्तिकर्ता और संभावित आपूर्तिकर्ता; वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, कर्मचारियों, आयकर विभाग के अधिकारियों और कई अन्य सरकारी हितों सहित व्यापार लेनदारों।

- इन सभी लोगों की रुचि है, यह सुनिश्चित करने में कि वे जिस वित्तीय विवरण का उपयोग करते हैं, और जिस पर वे भरोसा करते हैं, उद्यम की स्थिति और प्रगति की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करता है। प्रस्तुति का आधार उद्यम द्वारा अतीत में उपयोग किए गए अनुरूप होना चाहिए और अन्य समान उद्यमों द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ तुलनीय होना चाहिए।
- कुछ मामलों में, बाहरी व्यक्ति को आमतौर पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के ऊपर और ऊपर विशेष प्रयोजन के वित्तीय विवरणों के साथ आपूर्ति की जाएगी। हमारी आर्थिक प्रणाली की स्थिरता इस विश्वास पर निर्भर करती है कि उपयोगकर्ता समूहों में वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता है, जिस पर वे भरोसा करते हैं।
- यह एक सामान्य ढांचा प्रदान करके आत्मविश्वास की इस सामान्य भावना को बनाने के लिए लेखांकन मानकों का कार्य है जिसके भीतर विश्वसनीय वित्तीय विवरणों का उत्पादन किया जा सकता है। लेखा मानक मुख्य रूप से वित्तीय माप और प्रकटीकरण की प्रणाली के साथ सौदा करते हैं जो कि काफी प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के एक सेट के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उन्हें माप और प्रकटीकरण नियमों की एक प्रणाली के रूप में सोचा जा सकता है।
- वास्तव में, लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में क्या किया जाना चाहिए यह परिभाषित करने वाले एक कंकाल या ढाँचे से अधिक हैं। वे उन सीमाओं को भी आकर्षित करते हैं जिनके भीतर स्वीकार्य आचरण निहित है और उस में, और कई अन्य मामलों में, वे कानूनों के समान हैं।
- वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग करने के लिए प्रबंधन अपने आंतरिक मानकों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र है, और यह उद्यम के संचालन को नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण में उपयोग करता है। हालांकि, बाहरी उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए प्रबंधन द्वारा उत्पादित वित्तीय विवरण ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए जाते हैं जो प्रबंधन के लिए सीधे चिंता का विषय हैं।
- इस प्रकार, अन्य बातों के अलावा, प्रकाशित वित्तीय विवरण प्रबंधन की प्रभावशीलता की प्रभावशीलता को मापने में मदद करते हैं। वे कंपनी की लाभप्रदता को बनाए रखने और सुधारने में इसके कौशल का आकलन करने में मदद करते हैं, वे कंपनी की प्रगति, इसकी

शोधन क्षमता और तरलता को दर्शाते हैं, और आम तौर पर, वे अपने कर्तव्यों के प्रबंधन के प्रदर्शन की प्रभावशीलता का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण कारक हैं। और इसका नेतृत्व। इस प्रकार, प्रकाशित वित्तीय वक्तव्यों के प्रबंधन के पुरस्कारों और उद्यम में इसके शेयरधारिता के मूल्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना है।

- लेखांकन मानक भी विभिन्न बाहरी समूहों के बीच वित्तीय हित के संभावित संघर्षों को हल करने में महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हैं जो प्रकाशित वित्तीय वक्तव्यों का उपयोग और भरोसा करते हैं। ब्याज की ऐसी उलझनें लगातार और वास्तविक हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, संभावित शेयरधारकों और मौजूदा वास्तविक शेयरधारकों के पास कंपनी की लाभप्रदता और मूल्य का आकलन करने में विपरीत हित हो सकते हैं।
- संभावित शेयरधारकों के विघटित होने की संभावना है यदि वे प्रकाशित वित्तीय रिपोर्टों के बल पर शेयर खरीदते हैं जो बाद में आशावादी हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में बेचने वाले वर्तमान शेयरधारक परिणाम से अधिक संतुष्ट होने की संभावना रखते हैं, और निश्चित रूप से इससे अधिक संतुष्ट होते हैं यदि वे अनपेक्षित आशावादी वित्तीय रिपोर्टों के बल पर पकड़ बनाए रखते हैं।
- वित्तीय कठिनाइयों में चल रही कंपनी के मामले में शेयरधारकों और लेनदारों के बीच ब्याज के संभावित संघर्ष भी हो सकते हैं; और शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता, अक्सर कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन के उपायों के परिणाम में परस्पर विरोधी हित रखते हैं।
- इस प्रकार, लेखांकन मानकों को समाज में विभिन्न महत्वपूर्ण समूहों के बीच ब्याज की संभावित वित्तीय उलझनों के समाधान में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करने के रूप में देखा जा सकता है। यह इस प्रकार है कि यह आवश्यक है कि लेखांकन मानकों को इन सभी विभिन्न समूहों के बीच सबसे बड़ी संभव विश्वसनीयता का आदेश देना चाहिए।

## लेखांकन मानक के लाभ

- यह मानक पारदर्शी लेखांकन मानदंड विकसित करते हैं।
- यह हेरा-फेरी तथा छल-कपट की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर देता है।

- लेखांकन प्रमाप व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरणों के निर्माण व प्रस्तुतीकरण संबंधित विभिन्नताओं को बहुत सीमा तक कम करते हैं।
- यह प्रमाप कई तरह के पक्षकारों के हित की रक्षा करते हैं।
- लेखांकन मानक अंकेक्षक के लिए भी लाभप्रद होता हैं।

## माल और सेवा कर (GST)

माल और सेवा कर (Goods and services Tax) भारत में अप्रत्यक्ष कर है, जो पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहलिक पेय को छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है, इन पर अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग से कर लगाया जाता है। यह कर भारत सरकार द्वारा एक सौ और पहले संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ।

## जीएसटी की विशेषताएं

- पहले हम डायरेक्ट टैक्स के लिए हम वैट का इस्तेमाल किया जाता था किन्तु इसके स्थान पर माल और सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं
- जीएसटी के रूम केंद्र और राज्य को टैक्स को लागू और उसे लेने की शक्तिया है जिसमें केंद्र CGST और राज्य के द्वारा SGST केंद्र शाशित प्रदेश यानी UT में UTGST लागू होगा
- राज्य से बहार अगर सप्लाई की जायेगी तो उस पर IGST को लागू होगा जिससे क्रेडिट सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हो
- अगर आप माल को इम्पोर्ट यानी आयात करते हैं तो IGST के साथ सीमा शुल्क लगाया जाता है
- जीएसटी में इन को जीएसटी से बहार रखा गया है कच्चा तेल ,पेट्रोल ,डिजल ,ATF , और प्राकृतिक गैस
- तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी के साथ केंद्रय उत्पाद शुल्क भी लिया जाता है

## जीएसटी के लाभ

- कैस्केडिंग (व्यापक) प्रभाव को समाप्त करना।

जीएसटी लाभ के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत से कैस्केडिंग (व्यापक) प्रभाव को समाप्त करना था, और जैसा की आप जानते हैं, जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे एक छत्र के तहत अप्रत्यक्ष कराधान लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जीएसटी की शुरुआत ने कर के पिछले कैस्केडिंग प्रभाव को हटा दिया। क्योंकि वैट युग में, कर लगाने के लिए बहुत सारे कर लगाए जाते थे। जिससे ग्राहकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बहुत अधिक महंगा बना दिया। जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में तैयार किया गया था जिसने अन्य सभी करों को एकीकृत किया और कर पर प्रभाव को समाप्त कर दिया। कैस्केडिंग कर प्रभाव को टैक्स पर कर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

**आइए इस उदाहरण को समझते हैं कि टैक्स पर टैक्स क्या है:-** जीएसटी नियम से पहले एक सलाहकार ने 50,000 रुपये की सेवा की पेशकश की और 15% सेवा कर (50,000 रुपए \* 15% = 7,500 रुपए) लगाया। फिर कहते हैं, वह रुपये के लिए कार्यालय की आपूर्ति 20,000 रुपए में खरीदेगा। तो भुगतान पर 5% वैट कर (20,000 रुपये 5% = 1,000 रुपये)। उन्हें, पहले से ही भुगतान किए गए 1,000 रुपए वैट की कटौती के बिना स्टेशनरी पर 7,500 रुपए का आउटपुट भुगतान करना पड़ा। तो, उनका कुल बहिर्वाह 8,500 रुपये है। इसलिए जीएसटी के तहत:-

50,000 रुपये की सेवा पर 18% जीएसटी	9,000
कम: कार्यालय की आपूर्ति पर जीएसटी (रुपए 20,000*5%)	1,000
भुगतान करने के लिए कुल जीएसटी	8,000

- **पंजीकरण की उच्च सीमा।**

जीएसटी के फायदे और नुकसान के तहत जीएसटी शासन ने अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण की टर्नओवर सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले, वैट संरचना में, 5 लाख रुपये के कारोबार (ज्यादातर राज्यों में) के साथ कोई भी व्यवसाय वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। वही अब जीएसटी के तहत टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया थी, तथा

कई छोटे व्यवसायों और छोटे सेवा प्रदाताओं को छूट प्रदान करता है। व उत्तर पूर्वी राज्यों में जीएसटी पंजीकरण की टर्नओवर सीमा 10 लाख रूपए रखी गयी थी।

कर	कर की सीमा
एक्साइज	1.5 करोड़
वैट टैक्स	5 लाख ज्यादातर राज्यों में
सेवा कर	10 लाख
जीएसटी	40 लाख ( उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 20 लाख)

- **छोटे व्यवसायों के लिए संरचना योजना।**

छोटे व्यवसायों को जीएसटी के तहत रचना योजनाओं के साथ प्रदान किया जाता है। प्रत्येक छोटा-व्यवसाय जिसमें वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रूपए से 75 लाख रूपए कंपोजिशन स्कीम चुनने के योग्य हैं। इस योजना के माध्यम से, छोटे व्यवसाय कम दरों पर करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे जो उन पर कर अनुपालन के बोझ को और कम कर दिया है, यह भी एक बहुत बड़े फायदे के रूप में देखा जाता है।

- **सरल और आसान ऑनलाइन प्रक्रिया।**

जीएसटी के तहत पंजीकरण करने और रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के माध्यम से ऑनलाइन की गई है। इसने कर अनुपालन को बहुत आसान और सरल बना दिया है। वैट प्रणाली के विपरीत जहां अधिकांश प्रक्रियाएं शारीरिक रूप से पूरी हो गई थीं, जीएसटी प्रणाली अपने करदाताओं को अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति देती है। साथ ही, करदाताओं के लिए इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन उपलब्ध कराए गए हैं।

- **कम अनुपालन (अनुपालन की संख्या कम है)।**

जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों और उनकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत किया है। इसने दायर किए जाने वाले करों की संख्या कम कर दी है और अनुपालन भी। जीएसटी में

लगभग ग्यारह रिटर्न हैं जो इसके तहत दायर किए जाने हैं। इनमें से चार रिटर्न मूल रिटर्न हैं जो जीएसटी के तहत सभी करदाताओं के लिए लागू हैं। मुख्य रूप से GSTR-1 का विवरण मैनुअल रूप से दर्ज किया जाना है, जबकि GSTR-2 और GSTR-3 के रूप मुख्य रूप से ऑटो-आबादी वाले हैं। इससे पहले, वैट और सेवा कर था, जिनमें से प्रत्येक का अपना रिटर्न और अनुपालन था। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है:-

कर	टैक्स रिटर्न फाइलिंग
एक्साइज	प्रतिमाह
वैट टैक्स	कुछ राज्यों को कर-सीमा से अधिक मासिक रिटर्न की आवश्यकता होती है। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को मासिक रिटर्न की आवश्यकता है। (शर्त:-अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग)
सेवा कर	स्वामित्व / साझेदारी – त्रैमासिक कंपनी / एलएलपी – मासिक

#### • ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित उपचार।

जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों और उनकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत किया है। इसने दायर किए जाने वाले करों की संख्या कम कर दी है और अनुपालन भी। जीएसटी में लगभग ग्यारह रिटर्न हैं जो इसके तहत दायर किए जाने हैं। इनमें से चार रिटर्न मूल रिटर्न हैं जो जीएसटी के तहत सभी करदाताओं के लिए लागू हैं। मुख्य रूप से GSTR-1 का विवरण मैनुअल रूप से दर्ज किया जाना है, जबकि GSTR-2 और GSTR-3 के रूप मुख्य रूप से ऑटो-आबादी वाले हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट (जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न) उत्तर प्रदेश में डिलीवरी के लिए वैट की घोषणा करने और डिलीवरी ट्रक के पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने के लिए थीं। टैक्स

प्राधिकरण कभी-कभी सामानों को जब्त कर सकता है यदि दस्तावेज का उत्पादन नहीं किया गया था।

इन सभी विभेदक उपचारों और भ्रामक अनुपालन को GST के तहत हटा दिया गया है। पहली बार, जीएसटी ने ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू प्रावधानों को स्पष्ट रूप से हटा दिया है और चूंकि ये पूरे भारत में लागू हैं, इसलिए अब माल के अंतर-राज्य आंदोलन के बारे में कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए।

- **रसद की बेहतर दक्षता।**

इससे पहले, भारत में लॉजिस्टिक उद्योग को वर्तमान सीएसटी और राज्य-प्रवेश कर पर राज्य करों से बचने के लिए राज्यों भर में कई गोदामों को बनाए रखना होता था। इन गोदामों को उनकी क्षमता से नीचे संचालित करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे परिचालन लागत में वृद्धि हुई। जीएसटी के तहत, हालांकि, माल की अंतर-राज्य आवाजाही पर इन प्रतिबंधों में छूट दी गई है। जीएसटी के परिणामस्वरूप, गोदाम ऑपरेटरों और ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स खिलाड़ियों ने अपने डिलीवरी रूट पर हर दूसरे शहर के बजाय, नागपुर (जो भारत का एक शून्य मील शहर है) जैसे रणनीतिक स्थानों पर अपने गोदाम स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

**संक्षेप में कहे तो,** जीएसटी ने भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग को पहले की तुलना में अधिक कुशल बना दिया है। इससे राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हो गया है। गोदामों की संख्या कम हो गई है क्योंकि गोदाम संचालक और ई-कॉमर्स एग्रीगेटर अब रणनीतिक स्थानों में अपने गोदाम स्थापित करने के इच्छुक हैं। अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य चौकी की संख्या में कमी आई है, जिससे बहुत समय और धन की बचत होती है।

**संक्षेप में कहे तो,** जीएसटी ने भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग को पहले की तुलना में अधिक कुशल बना दिया है। इससे राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हो गया है। गोदामों की संख्या कम हो गई है क्योंकि गोदाम संचालक और ई-कॉमर्स एग्रीगेटर अब रणनीतिक स्थानों में अपने गोदाम स्थापित करने के इच्छुक हैं। अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य चौकी की संख्या में कमी आई है, जिससे बहुत समय और धन की बचत होती है।

- असंगठित क्षेत्र को विनियमित किया जाता है।

पूर्व-जीएसटी युग में इसका असंगठित क्षेत्र काफी हद तक अनियमित था। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान स्वीकार किए जाने के बाद, GST ने इस असंगठित क्षेत्र को ऑनलाइन अनुपालन, ऑनलाइन भुगतान, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जैसे प्रावधानों के साथ प्रदान किया। इसने असंगठित क्षेत्र को अधिक जवाब देह और व्यवस्थित रूप से विनियमित किया है। अन्य जीएसटी लाभों में पारदर्शिता में वृद्धि, व्यापार करने की कम लागत, उत्पादन में वृद्धि, परिवहन में कम समय आदि शामिल हैं।



# Fukey Education

## NCERT SOLUTIONS

### प्रश्न (पृष्ठ संख्या 47 - 48)

#### लघुउत्तरीय प्रश्न:

प्रश्न 1 एक व्यावसायिक इकाई सतत् इकाई रहेगी। एक लेखाकार की यह परिकल्पना क्यों आवश्यक है?

उत्तर – लेखांकन की सतत् व्यापार (Going Concern) संकल्पना के आधार पर यह माना जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक निरन्तर चलता रहेगा तथा कभी बन्द नहीं होगा जब तक कि कोई ऐसा कारण या कोई विपरीत स्थिति न हो। इस परिकल्पना के अनुरूप यह मान कर चला जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा फिर भी प्रतिवर्ष आर्थिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए लेखा विवरण अथवा प्रतिवेदन सामयिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसी आधार पर सम्पत्तियों पर मूल्य हास की गणना में सम्पत्ति के उपयोगी जीवन काल को ध्यान में रखा जाता है न कि उसके चालू मूल्य को।

प्रश्न 2 आमद को मान्य कब माना जायेगा? क्या इसके सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं?

उत्तर – आगम मान्यता संकल्पना के अनुसार किसी भी आमद को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलिखित नहीं करना चाहिए जब तक कि वह वास्तविक रूप में प्राप्त न हो जाए। यहाँ आगम या आमद से तात्पर्य रोकड़ के उस कुल अन्तर्ग्रवाह से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के संसाधनों का दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश आदि से है।

आगम या आमद को मान्य तभी माना जा सकता है जब उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय का विधिसम्मत अधिकार हो जाता है। अर्थात् जब वस्तुओं का विक्रय हो चुका हो अथवा सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हों। उदाहरणार्थ, उधार विक्रय को आगम विक्रय की तिथि से मान लिया जाता है न कि उसके भुगतान की तिथि को। इसी प्रकार किराया, कमीशन, ब्याज आदि आयों को समय के आधार पर मान्य माना जाता है चाहे यह लेखा वर्ष के अन्त तक प्राप्त न हो अथवा यदि आगामी लेखा वर्ष से

संबंधित अवधि की राशि भी प्राप्त हो गई हो तो उसका समायोजन करके इस वर्ष में इस वर्ष से संबंधित राशि को ही सम्मिलित करते हैं।

प्रश्न 3 आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है?

उत्तर – आधारभूत लेखांकन समीकरण (Basic Accounting Equation):

आधारभूत लेखांकन समीकरण द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार का दोहरा लेखा किया जाता है अर्थात् डेबिट व क्रेडिट पक्ष में। प्रत्येक संस्था में सम्पत्ति पक्ष का योग दायित्व पक्ष के योग के बराबर होता है। उपर्युक्त तथ्य को जब एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे ही लेखांकन समीकरण कहते हैं।

आधारभूत लेखांकन समीकरण

1. सम्पत्तियाँ = पूँजी + दायित्व (Assets = Capital + Liabilities)
2. दायित्व = सम्पत्तियाँ - पूँजी (Liabilities = Assets - Capital)
3. पूँजी = सम्पत्तियाँ - दायित्व (Capital = Assets - Liabilities)

प्रश्न 4 आगम मान्यता संकल्पना यह निर्धारित करती है कि किसी लेखावर्ष के लिए लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए ग्राहकों को उधार बेचे गये माल को विक्रय में सम्मिलित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा व्यवहार में यह निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अवधि में किसी लेन-देन को कब सम्मिलित किया जाए। वस्तुओं के (अ) प्रेषण पर, (ब) सुपुर्दगी पर, (स) बीजक भेज देने पर, (द) भुगतान प्राप्त होने पर। अपने उत्तर का कारण भी दें। उत्तर – लेखाकार के सामने आय सम्बन्धी अनेक समस्याएँ आती हैं उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि किसी विशिष्ट आय को किस स्थिति में यह मान लेना चाहिए कि व्यवसाय ने उसको अर्जित कर लिया है। उदाहरण के रूप में माल की उधार बिक्री के व्यवहार की स्थिति में निम्न परिस्थितियों में से किस स्थिति पर बिक्री को आय के रूप में पहचान कर लेखों में सम्मिलित किया जाए:

1. प्रेषण के समय (At the time of despatch of goods),
2. माल सुपुर्दगी के समय (At the time of delivery of goods),
3. बीजक भेज देने पर (At the time of sending bill),

#### 4. भुगतान के समय (At the time of receipt of payment)।

नकद बिक्री की स्थिति में माल की सुपुर्दगी व भुगतान समय में अन्तर न होने के कारण आगम उपार्जन निर्धारण की समस्या उत्पन्न नहीं होती तथापि उधार बिक्री में प्रायः ऐसी समस्याएँ आती हैं। इस सम्बन्ध में सामान्यतः माल की सुपुर्दगी पर ही इसे बिक्री मानकर संस्था की आय उपार्जन का निर्धारण किया जाता है।

प्रश्न 5 संकल्पना पहचानिए:

1. यदि एक फर्म को यह लगता है कि उसके कुछ देनदार भुगतान नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में अनुमानित हानियों के लिए यदि वह पहले से ही लेखा-पुस्तकों में प्रावधान कर लेती है तो यह ..... संकल्पना का उदाहरण
2. व्यवसाय का अस्तित्व अपने स्वामी से भिन्न है तथ्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ..... संकल्पना है।
3. प्रत्येक वस्तु जिसका स्वामी फर्म है, का स्वामित्व किसी और व्यक्ति के पास भी है। यह संयोग ..... संकल्पना में वर्णित है।
4. यदि संपत्तियों पर मूल्य ह्रास की गणना के लिए सीधी रेखा विधि का प्रयोग किया गया है तो ..... संकल्पना के अनुसार इसी विधि का प्रयोग अगले वर्ष भी किया जाना चाहिए।
5. एक फर्म के पास ऐसा स्टॉक जिसकी बाजार में माँग है। परिणामतः बाजार में उस माल का मूल्य बढ़ गया है। साधारण लेखांकन पद्धति में हम इस मूल्य वृद्धि पर ..... संकल्पना के अन्तर्गत ध्यान नहीं देंगे।
6. यदि किसी फर्म को वस्तुओं के विक्रय का आदेश मिलता है तो ..... संकल्पना के अन्तर्गत उसको कुल विक्रय के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
7. किसी फर्म का प्रबन्धक बहुत अकुशल है लेकिन लेखाकार इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को लेखा-पुस्तकों में ..... संकल्पना के कारण वर्णित नहीं कर सकता।

उत्तर –

1. रूढ़िवादिता (विवेकशीलता)

2. व्यावसायिक इकाई
3. द्विपक्षीय
4. समनुरूपता
5. लागत
6. आगम मान्यता
7. मुद्रा मापन।

### निबन्धात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1 साधारणतः लेखांकन संकल्पनाओं व लेखांकन मानकों को वित्तीय लेखांकन का सार कहा जाता है। " टिप्पणी कीजिए।

उत्तर - साधारणतः मान्य लेखांकन संकल्पनाएँ: ये वे सिद्धान्त एवं नियम हैं जिनका विकास लेखांकन अभिलेखों में समनुरूपता व एकरूपता लाने के लिए किया गया है तथा जिन्हें इस पेशे से जुड़े सभी लेखाकारों की सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इन नियमों को विभिन्न नामों जैसे - सिद्धान्त, संकल्पना, परिपाटी, अवधारणा, परिकल्पनाएँ, संशोधक सिद्धान्त आदि से भी जाना जाता है।

सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों (GAAP) से आशय वित्तीय विवरणों के लेखन, निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त उन सभी नियमों व निर्देशक क्रियाओं से हैं जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है।

जैसे एक महत्त्वपूर्ण नियम के अनुसार वित्तीय लेखांकन में सभी लेन-देनों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, साथ ही इन लेन-देनों का सत्यापन मुद्रा भुगतान से प्राप्त नकद रसीद द्वारा होना भी आवश्यक है। ऐसा करने से अभिलेखन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ बनती है तथा लेखांकन विवरण विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिक स्वीकार्य हो जाते हैं।

इन संकल्पनाओं का विकास एक लम्बी अवधि में पूर्व अनुभवों, प्रयोगों अथवा परम्पराओं, व्यक्तियों एवं पेशेवर निकायों के विवरणों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा नियमन के आधार पर हुआ है तथा यह अधिकांश पेशेवर लेखाकारों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत है। लेकिन ये नियम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, वैधानिक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से प्रभावित हो निरन्तर परिवर्तित

होते रहते हैं। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन साधारणतः मान्य लेखांकन संकल्पनाओं पर आधारित होता है।

लेखांकन मानक (Accounting Standard): लेखांकन मानक लेखांकन के नियमों, निर्देशों व अभ्यासों के संबंध में वह लिखित वाक्यांश है जो लेखांकन सचना के प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समनुरूपता व एकरूपता लाते हैं। ये वे नीतिगत प्रलेख हैं जो वित्तीय विवरणों में लेखांकन लेन-देनों की पहचान, मापन, व्यवहार, प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटीकरण के आयामों को आवरित करते हैं।

लेखांकन मानक आई.सी.ए.आई., जो हमारे देश में लेखांकन की पेशेवर संस्था है, द्वारा जारी किए गए प्राधिकारिक विवरण हैं। लेकिन मानकों की आड़ में देश के व्यावसायिक वातावरण, प्रचलित कानून, परंपराओं आदि की अवहेलना नहीं की जा सकती। वित्तीय लेखांकन, लेखांकन संकल्पनाओं तथा लेखांकन मानकों पर ही आधारित होता है। अतः लेखांकन संकल्पनाओं व लेखांकन मानकों को वित्तीय लेखांकन का सार कहा जाता है।

प्रश्न 2 वित्तीय लेखांकन में समनुरूप आधारों का पालन क्यों आवश्यक है?

उत्तर – समनुरूपता (Consistency) की संकल्पना वित्तीय विवरणों में अन्तर-आवधिक व अन्तर-फर्मीय तुलनीयता के लिए यह आवश्यक है कि किसी एक समय में व्यवसाय में लेखांकन के समान अभ्यासों व नीतियों का प्रयोग हो। तुलनीयता तभी संभव होती है जबकि तुलना की अवधि में विभिन्न इकाइयां अथवा एक ही इकाई विभिन्न समयावधि में समान लेखांकन सिद्धांत को समान रूप से प्रयोग कर रही हो।

इस बात को समझने के लिए मान लीजिए एक निवेशक व्यवसाय विशेष के वर्तमान वर्ष के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना पिछले वर्ष के प्रदर्शन से करना चाहता है। इसके लिए वर्तमान वर्ष के शुद्ध लाभ की तुलना पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ से कर सकता है। लेकिन यदि पिछले वर्ष हास के निर्धारण की लेखांकन नीति व इस वर्ष की नीति में अंतर है तो क्या यह लाभ तुलनीय होंगे।

यही स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है यदि दोनों वर्षों में स्टॉक के मूल्यांकन के लिए भी अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण यह अति आवश्यक है कि समनुरूपता की

संकल्पना का पालन हो ताकि दो भिन्न लेखांकन अवधियों के परिणामों की तुलना की जा सके। समनुरूपता व्यक्तिगत आग्रह का भी निराकरण करती है तथा परिणामों को तुलनीय बनाती है।

ऐसा नहीं है कि समनुरूपता की संकल्पना लेखांकन नीतियों में परिवर्तन वर्जित करती हो लेकिन यह आवश्यक है कि इनमें किसी भी परिवर्तन की सम्पूर्ण सूचना विवरणों में उपलब्ध हो तथा इनके कारण परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट रूप से इंगित किए जाएँ। इसी प्रकार दो व्यवसायों के वित्तीय परिणामों की तुलना भी तभी संभव है यदि दोनों ने वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए लेखांकन के समान तरीके व नीतियों का पालन किया हो।

लेखांकन में अनेक व्यवहार व्यक्तिनिष्ठता से अधिक प्रभावित होते हैं। समय एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रचलित पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे हास की रीतियाँ, संचय एवं आयोजन, काल्पनिक सम्पत्तियों का अपलेखन आदि। लेखा अवधि के आधार में ऐसा परिवर्तन लेखों की तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है जो विभिन्न पक्षकारों के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना यदि निर्णय लिए गए तो अत्यन्त खतरनाक होते हैं। इसी आधार पर पिछले कुछ वर्षों से लेखा अवधि के रिकॉर्डों में एकरूपता रखने पर काफी ओर दिया जा रहा है।

लेखापाल को चाहिए कि जिस पद्धति या विकल्प का एक बार चुनाव कर लिया जाए, यथासम्भव उसमें परिवर्तन नहीं करे। यदि परिवर्तन अवश्यम्भावी हो तो इस प्रकार के परिवर्तन एवं उसके अन्तिम डने वाले प्रभाव को टिप्पणी के रूप में अवश्य दिखाया जाए अर्थात् अपनाई जाने वाली पद्धति में 'स्थिरता' एवं 'एकरूपता' (Consistency) होनी चाहिए ताकि लेखों में संगति व तुलनात्मकता बनी रहे। इस तरह लेखों में सम्बन्धित पक्षों का विश्वास भी बढ़ता है।

उदाहरणार्थ, स्टॉक के मूल्यांकन (Valuation of Stock) में 'लागत एवं बाजार मूल्य' में कम पद्धति को अपनाकर उसे केवल बाजार मूल्य पर दिखाने की पद्धति अपनाना ठीक नहीं होगा। भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार लेखा नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कम्पनी के वार्षिक खातों में दिखाना अनिवार्य है।

प्रश्न 3 एक लेखापाल के लिए लाभों का अनुमान जरूरी नहीं है अपितु प्रत्येक हानि का प्रावधान अति आवश्यक है। इस तथ्य का अनुमोदन करने वाली संकल्पना की विवेचना कीजिए।

उत्तर – अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की संकल्पना (Concept of Conservatism): लेखांकन करते समय सम्पत्ति, दायित्व तथा आय से सम्बन्धित मदों के मूल्यांकन के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। विकल्पों का चयन करते समय अनुदारवादी परम्परा की पालना करनी चाहिए। इस संकल्पना में यह बताया गया है कि व्यवसाय में होने वाली सम्भावित हानियों की पहले से ही व्यवस्था कर ली जाए परन्तु भावी लाभों की सम्भावना पर ध्यान नहीं रखा जाए। इसीलिए व्यापारी संदिग्ध हानियों के लिए आयोजन करते हैं व अदृश्य सम्पत्तियों (ख्याति, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट) को शीघ्र अपलिखित करते हैं तथा स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो, पर करते हैं।

इस संकल्पना के अनुसार समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित न हो लेकिन वह सभी हानियां जिनकी यदि दूरस्थ संभावना भी हो, तो उनके लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान कर लेना चाहिए। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य व बाजार मूल्य में से जो कम है उस पर करना तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आरंभ से ही प्रावधान, देनदारों के लिए छूट का प्रावधान, अमूर्त संपत्तियों ख्याति, पेटेंट आदि। का सामयिक अपलेखन आदि इसी संकल्पना के उपयोग के उदाहरण हैं।

इसी कारण यदि बाजार में क्रय किए गए माल का मूल्य कम हो गया है तो लेखा-पुस्तकों में उसे खरीद के मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। इसके विपरीत यदि बाजार में माल का मूल्य बढ़ गया है तो लाभ का कोई लेखा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि माल को बेच न लिया जाये। इसलिए यह अभिगम जिसमें हानियों के लिए प्रावधान आवश्यक है लेकिन लाभों की पहचान तब तक नहीं होती जब तक कि उनका वास्तविक अर्जन न हो, विवेकशीलतापूर्ण लेखांकन कहलाता है।

यह शायद लेखाकारों के निराशापूर्ण दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है, लेकिन यह व्यवसाय की अनिश्चितताओं से निपटने तथा देनदारों के हितों की फर्म की परिसम्पत्तियों के अवांछनीय वितरण से सुरक्षा प्रदान करने की कारगर विधि है। फिर भी जानबूझकर परिसम्पत्तियों को कम मूल्य पर आंकने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप छुपे हुए लाभ अर्थात् गुप्त कोषों का निर्माण हो जाएगा।

लेखांकन में इस संकल्पना के निम्नलिखित उदाहरण हैं:

- अनिश्चित जीवन काल वाली अमूर्त सम्पत्तियों, जैसे ख्याति को अपलिखित करना;
- हास की सीधी रेखा पद्धति की तुलना में अपलिखित मूल्य विधि को अपनाना;
- लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन न करना;
- स्टॉक का लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, पर मूल्यांकन करना;
- डूबत एवं संदिग्ध ऋणों तथा बट्टे के लिए देनदारों पर आयोजन का निर्माण करना;
- ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का उनके निर्गमन के समय ही प्रावधान करना;
- विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ावों के लिए आयोजन करना;
- संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को, प्रीमियम की चुकाई गई राशि के बजाय समर्पण मूल्य पर चिट्ठे में दिखाना।

प्रश्न 4 आगम-व्यय मिलान संकल्पना से आप क्या समझते हैं? एक व्यवसाय के लिए इसका पालन क्यों आवश्यक है?

उत्तर – आगम-व्यय मिलान (Matching) संकल्पना: इस संकल्पना में लेखांकन अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से करने पर बल दिया जाता है। इसी के परिणामस्वरूप इन आगमों को अर्जित करने के लिए जो व्यय किये गये हैं वह उसी लेखावर्ष से संबंधित होने चाहिए। यह जानने की प्रक्रिया में, कि एक दिए गए अंतराल में व्यवसाय ने लाभ अर्जित किया है या उसे हानियाँ उठानी पड़ी हैं, हम उस अन्तराल विशेष की आमदनी में से व्ययों को घटाते हैं।

आगम व्यय मिलान संकल्पना में लेखांकन के इसी पक्ष पर बल दिया जाता है। इस संकल्पना के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाना चाहिए। आगम को मान्य या अर्जित तभी मान लिया जाता है जब विक्रय हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है न कि जब उसके प्रतिफल के रूप में रोकड़ प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार एक व्यय को भी तभी खर्च मान लिया जाता है जब उससे किसी संपत्ति या आगम का अर्जन हो गया हो, न कि जब उस पर रोकड़ का भुगतान हुआ।

उदाहरणार्थ वेतन, किराया, बीमा आदि का व्यय जिस समय वह देय है, के अनुसार ही खर्च मान लिया जाता है न कि जब वास्तविक रूप में इनका भुगतान किया जाए। इसी प्रकार स्थिर संपत्तियों पर हास निकालने के लिए संपत्ति के मूल्य को उसकी उपयोगिता के वर्षों से भाग दिया जाता लेखांकन यदि उपार्जन आधार पर किया जाए तो आगम व लागतों को लेन-देन के समय ही मान्यता दी जाती है न कि उनके वास्तविक प्राप्ति या भुगतान के समय। नकद प्राप्ति व नकद प्राप्ति के अधिकार और नकद भुगतान व नकद भुगतान के वैधानिक अनिवार्यता के बीच अंतर किया जाता है।

इसलिए इस प्रणाली के अनुसार लेन-देन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में इसके उपार्जन के समय के अनुसार किया जाता है न कि इसके बदले में वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। यह व्यवसाय के लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है क्योंकि इसके अनुसार आगम व व्ययों का मिलान संभव है। उदाहरणार्थ, बेचे गए माल की लागत का मिलान उपयोग किए गए कच्चे माल से किया जा सकता है। अंत में आगम व्यय मिलान संकल्पना के अनुसार किसी वर्ष विशेष के लाभ व हानि की गणना करने के लिए उस अवधि के सभी आगम चाहे उनके बदले रोकड़ मिली है या नहीं तथा सभी व्यय चाहे उनके बदले रोकड़ भुगतान हुआ है या नहीं, का अभिलेखन आवश्यक है।

प्रश्न 5 मुद्रा मापन संकल्पना का क्या अभिप्राय है? वह एक तत्व बताइए जिसके कारण एक वर्ष के मुद्रा मूल्यों की तुलना दूसरे वर्ष के मुद्रा मूल्यों से करने में कठिनाई आ सकती है।

उत्तर - मुद्रा मापन संकल्पना (Money Measurement Concept): मुद्रा मापन की संकल्पना के अनुसार संगठन की लेखांकन पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन-देनों व घटनाओं का वर्णन अथवा लेखांकन होगा जिनकी प्रस्तुति मुद्रा की इकाइयों के रूप में हो सकती है, साथ ही लेन-देनों का ब्यौरा केवल मौद्रिक इकाइयों में रखा जाएगा, न कि भौतिक इकाइयों में। मुद्रा मापन की संकल्पना यह उल्लेख करती है कि किसी संगठन में केवल उन्हीं लेन-देनों या घटनाओं (जिनका लेखन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, जैसे-वस्तुओं का विक्रय, व्ययों का भुगतान अथवा किसी आय की प्राप्ति आदि) का ही अभिलेखन लेखा-पुस्तकों में किया जाएगा।

वह सभी लेन-देन या घटनाएं जिनको मुद्रा के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे - प्रबन्धक की नियुक्ति या संगठन के मानव संसाधन की योग्यताएं अथवा शोध विभाग की सृजनशीलता व

साधारणजन में संगठन की प्रतिष्ठा आदि महत्त्वपूर्ण सूचनाएं व्यापार के लेखांकन अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं करते।

उदाहरणार्थ, किसी व्यवसायी के पास भवन, मशीन, कच्चा माल, पेटेण्ट, मोटरकार, प्लाण्ट, फर्नीचर आदि के रूप में सम्पत्तियाँ हैं तथा उनके आधार पर उस व्यवसायी की आर्थिक स्थिति ज्ञात करनी है, तो ऐसी स्थिति में इन समस्त सम्पत्तियों का मूल्य मुद्रा में आंका जाएगा और उनके मौद्रिक मूल्यों के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति व्यक्त की जाएगी।

इस अवधारणा का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि एक आम आदमी भी व्यवसाय के विभिन्न पक्षों को आसानी से जान सकता है यदि उन्हें मुद्रा मूल्यों में व्यक्त किया जाए। मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण एक वर्ष के मुद्रा मूल्यों की तुलना दूसरे वर्ष के मुद्रा मूल्यों से करने में कठिनाई मुद्रा मापन की संकल्पना सीमाओं से मुक्त नहीं है। कुछ समय के पश्चात् मूल्यों में परिवर्तनों के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन होता रहता है।

आज बढ़ते हुए मूल्यों के कारण रुपये का मूल्य आज से दस वर्ष पूर्व के मूल्य की तुलना में काफी कम है। इसलिए तुलन पत्र में जब हम अलग-अलग समय पर खरीदी गई परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य जोड़ते हैं जैसे कि 2005 में खरीदा गया 1 करोड़ का भवन, 2019 में खरीदा गया 2 करोड़ का संयन्त्र तो हम मूलतः दो भिन्न तथ्यों के मूल्यों को जोड़ रहे हैं जबकि इन्हें एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि स्थिति विवरण में मुद्रा के मूल्य में आ रहे परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित नहीं किया जाता इसलिए यह लेखांकन आंकड़े बहुधा व्यापार का सत्य व सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर पाते।

इस संकल्पना की कुछ सीमाएँ निम्न प्रकार हैं:

1. व्यापार की समस्त सम्पत्तियों को मुद्रा मूल्यों में मापना सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ-किसी व्यापार की ख्याति को मुद्रा मूल्यों में सही-सही मापा नहीं जा सकता।
2. मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मुद्रा का मूल्य उस देश की मुद्रास्फीति की दर के अनुसार बढ़ता व घटता है। इससे एक वर्ष के मुद्रा मूल्यों की तुलना दूसरे वर्ष के मुद्रा मूल्यों से करने में कठिनाई आ सकती है।